फ़ाइल संख्या-15011/36/2022-न्याय/ई 6889
भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग

विषयः न्याय विभाग से संबंधित मई, 2023 माह का मासिक सार

न्याय विभाग से संबंधित मई, 2023 माह की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं

1. **<u>ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना चरण-II</u>**

(i) एनजेडीजी: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर, दिनांक 1.5.2023 तक की स्थिति के अनुसार, 22.89 करोड़ से अधिक मामलों और कम्प्यूटरीकृत अदालतों से संबंधित 21.52 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(ii) वर्चुअल कोर्ट: 21 वर्चुअल कोर्ट द्वारा 2.95 करोड़ से अधिक मामलों को निपटाया गया है और दिनांक 30.04.2023 तक 36 लाख से अधिक मामलों में 396 करोड़ रुपये का ऑनलाइन जुर्माना वसूल किया गया है।

(iii) ई-कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप: दिनांक 30.04.2023 तक ई-कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप डाउनलोड की कुल संख्या 1.79 करोड़ तक पहुंच गई है।

(iv) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग: दिनांक 30.4.2023 तक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके जिला और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा (लगभग 1.93 करोड़) और उच्च न्यायालयों द्वारा (लगभग 78 लाख) कुल लगभग 2.71 करोड़ मामलों की सुनवाई की गई। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 15.05.2023 तक लगभग 4.83 लाख मामलों की सुनवाई की।

(v) ई-सेवा केंद्र: दिनांक 30.04.2023 तक 25 उच्च न्यायालयों के अधीन 795 ई-सेवा केंद्र कार्यात्मक बनाए जा चुके हैं ।

2. **<u>2. टेली-लॉ: वंचितों तक पहुंच</u>**

(क) 31 मई 2023 तक 2,81,345 कुल 40,94,484 लाभार्थियों को कानूनी सलाह प्रदान की गई जिसमें मई 2023 माह के 2,81,345 लाभार्थी भी शामिल हैं।

(ख) माह के दौरान, ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई)/अर्ध विधिक स्वयंसेवकों (पीएलवी), राज्य समन्वयकों और पैनल वकीलों द्वारा 101 जिलों में आयोजित 122 प्रशिक्षणों और जागरूकता सत्रों/शिविरों में 3377 व्यक्तियों ने भाग लिया।

3 **<u>. न्याय बंधु (प्रो-बोनो लीगल सर्विसेज) कार्यक्रम :</u>**

माह के दौरान, 99 नए प्रो बोनो अधिवक्ताओं ने न्याय संधू मोबाइल एप्लिकेशन/वेब पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराया। कुल 10,117 वकीलों (पुरुष-8493, महिला-1622, ट्रांसजेंडर-02) ने न्याय बंधु पोर्टल के तहत पंजीकरण कराया है। .

4. <u>कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता (एलएलएलएपी):</u>

(i) माह के दौरान, अरुणाचल प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा छह जिलों - अंजॉ , चांगलांग , पक्केकेसांग, पापुम पारे, निचली दिबांग घाटी और तिरप के गांवों में कानूनी जागरूकता अभियान आयोजित किए गए; प्रशिक्षित गांव वृद्धों और वृद्धाओं के साथ 614 लोगों तक पहुंचा गया।

(ii) (ii) विधि अनुसंधान संस्थान (एलआरआई), गौहाटी, असम ने 27 मई 2023 को असम प्रशासनिक स्टॉफ कॉलेज, गुवाहाटी में 6 जनजातियों- सोरो , तिवा , राभा , ज़ेमे नागा, हलम और निशी के सदस्यों और पीठ एवं बार, गैर सरकारी संगठनों और मीडिया से आए सदस्यों सहित कुल 150 व्यक्तियों के लिए "उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रथागत कानूनों के दस्तावेज़ीकरण का महत्व" पर एक प्रसार कार्यशाला सह संगोष्ठी का आयोजन किया।

(iii) सेंटर फॉर कम्युनिटी इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स सोसायटी, जयपुर, राजस्थान ने राजस्थान के धौलपुर जिले के सरमथुरा और बाडी ब्लॉक में 9 पंचायत स्तरीय संवेदीकरण सत्र, 16 धानी बैठकें, पंचायत स्तरीय संवेदीकरण सत्र और जन जागरूकता अभियान आयोजित किए।

*****